भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1428
जिसका उत्तर मंगलवार, 03 मई, 2016 को दिया जाना है।

फेम इंडिया के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बस

1428. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय राज्यों में अपनी फ्लैगशिप योजना, फेम इंडिया (फास्टर एडोपसन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया) के अंतर्गत जीरो इमिशन रेडोफिटिड इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की अनुमति प्रदान की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत संवितरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित/मंजूर की गई है;
(ग) क्या देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड फॉर व्हीलर्स वाहनों की मांग कम है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए इस समस्या का समाधान किस तरीके से करेगी;
(ङ) यदि यह योजना लागू की जाती है तो क्या इससे सरकार वार्षिक रूप से तेल आयात बिल में बचत करेगी; और
(च) क्या इस परियोजना में निवेश की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): जी, हां। प्रारंभ में, मांग प्रोत्साहन न होने की वजह से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की मांग कम थी। तथापि, फेम इंडिया स्कीम की शुरुआत होने से, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की मांग बढ़नी शुरू हुई है।

(ङ): जी, हां। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के अनुसार, यदि वर्तमान स्कीम 2020 तक जारी रहती है तो अनुमान है कि लगभग ₹62000 करोड़ की कीमत के 9500 मिलियन लीटर कच्चे तेल की बचत होगी।

(च): कोई निवेश प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

****